भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5336

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना

5336. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी स्वीकृत, निर्माणाधीन और परिचालनरत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (एमएमएलपी) का स्थान, भूमि क्षेत्र और कार्यान्वयन एजेंसी सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति की तिथियां, बोली आरंभ करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने, निर्माण शुरू होने और अपेक्षित पूरा होने की समय-सीमा सहित प्रत्येक एमएमएलपी की समय-सीमा क्या है;

(ग) भारतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत एमएमएलपी की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और देरी के कारण, यदि कोई हो, क्या हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक एमएमएलपी के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई;

(ङ) क्या कोई लागत वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन एमएमएलपी द्वारा अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य-वार और परियोजना-वार कितने रोजगार सृजित किए गए हैं;

(छ) क्या किसी एमएमएलपी को भूमि अधिग्रहण/पर्यावरणीय मंजूरी/निजी निवेश की कमी के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इन चुनौतियों को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) क्या सरकार ने माल ढुलाई लागत और पारगमन समय में अपेक्षित कमी का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) देश भर में विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए पूरे भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए 35 स्थानों को मंजूरी

दी है, तथा इससे लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आने की उम्मीद है। स्वीकृत किए गए स्थानों में से जोगीघोपा, चेन्नई, बेंगलुरू, नागपुर और इंदौर में स्थित (05) एमएमएलपी विकासाधीन हैं और वित्त वर्ष 2026-27 में इनके परिचालन में आने की उम्मीद है। स्थान, भूमि क्षेत्रफल, कार्यान्वयन एजेंसी, समयसीमा के बारे में विवरण **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(घ) विकासाधीन 05 एमएमएलपी के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) एमएमएलपी, जोगीघोपा के संबंध में अब तक केवल 38.28 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है ।

(च) चूंकि अभी तक कोई एमएमएलपी चालू नहीं हुई है, इसलिए सृजित रोजगार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(छ) एमएमएलपी के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से, एमएमएलपी, जोगीघोपा के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में 384 दिनों की देरी हुई थी। पर्यावरणीय मंज़ूरी मिलने में अब तक कोई खास देरी नहीं हुई है।

(ज) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अनुसार, लॉजिस्टिक्स/माल ढुलाई लागत में अपेक्षित कमी जीडीपी के मौजूदा 13-14 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 8-9 प्रतिशत हो जाएगी।

अनुबंध I

"मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना" के संबंध में श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5336 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	एमएमएलपी परियोजना का नाम	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	क्रियान्वयन एजेंसी	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यवहार्यता अध्ययन	बोली की शुरुआत	अनुमोदन	निर्माण का प्रारंभ	वर्तमान स्थिति
1.	चेन्नई, तमिलनाडु	181.00	मैसर्स रिलायंस मप्पेडु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	जनवरी 2022	21.01.2022	06.06.2022	15.02.2024	वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद
2.	नागपुर, महाराष्ट्र	400.00	मैसर्स पाथ बेंगलुरु लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड	दिसंबर 2021	10.12.2021	27.05.2022	11.07.2024	
3.	इंदौर, मध्य प्रदेश	255.00	मैसर्स जीआर लॉजिस्टिक्स पार्क (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड	सितंबर 2022	30.09.2022	27.02.2023	21.11.2024	
4.	बेंगलुरु, कर्नाटक	150.04	मैसर्स डीसी मल्टी मॉडल पार्क (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड	दिसंबर 2022	15.12.2022	18.06.2022	30.11.2024	
5.	जोगीघोपा , असम	200	एनएचआईडीसीएल	मार्च 2020	07.03.2020	03.02.2020	05.06.2020	वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद

अनुबंध II

"मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना" के संबंध में श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5336 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एमएमएलपी के स्थान</th><th>परियोजना की अनुमानित लागत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>*चेन्नई</td><td>
<table>
<tr><th>रियायतग्राही का हिस्सा करोड़ रुपए में</th><th>प्राधिकरण का हिस्सा करोड़ रुपए में (भारत सरकार, सीएचपीए, टीआईडीसीओ और आरवीएनएल)</th><th>कुल लागत (प्राधिकरण +रियायतग्राही)</th></tr>
<tr><td>782.58 करोड़ रु.</td><td>640.92 करोड़ रु.</td><td>1423.50 करोड़ रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>*बेंगलुरु</td><td>
<table>
<tr><th>रियायतग्राही का हिस्सा करोड़ रुपए में</th><th>प्राधिकरण का हिस्सा करोड़ रुपए में (भारत सरकार, केआईएडीबी और आरवीएनएल)</th><th>कुल लागत (प्राधिकरण +रियायतग्राही) करोड़ रु. में</th></tr>
<tr><td>935.90 करोड़ रु.</td><td>833.80 रु.</td><td>1769.70 करोड़ रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>*इंदौर</td><td>
<table>
<tr><th>रियायतग्राही का हिस्सा करोड़ रुपए में</th><th>प्राधिकरण का हिस्सा करोड़ रुपए में (भारत सरकार, एमपीआईडीसी और आरवीएनएल)</th><th>कुल लागत (अधिकार +रियायतग्राही) करोड़ रु. में</th></tr>
<tr><td>758.10 रु.</td><td>352.59 रु.</td><td>1110.69 करोड़ रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>*नागपुर</td><td>
<table>
<tr><th>रियायतग्राही का हिस्सा करोड़ रुपए में</th><th>प्राधिकरण का हिस्सा करोड़ रुपए में (भारत सरकार और जेएनपीए)</th><th>कुल लागत (प्राधिकरण +रियायतग्राही)</th></tr>
<tr><td>352.97 करोड़ रु.</td><td>320.15 रु.</td><td>673.12 करोड़ रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जोगीघोपा</td><td>
<table>
<tr><th>स्वीकृत लागत</th><th>आवंटन/ व्यय</th></tr>
<tr><td>693.97 करोड़ रु.</td><td>451.42 करोड़ रु.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

*****